# चीन की सैन्य बढ़त

कुछ दिन पहले आपसी बातचीत का हवाला देते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने बताया था कि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की बढ़त से चिंतित हैं. इस चिंता से सहमति जताते हुए उन्होंने दोनों देशों की तुलना करते हुए यह भी कहा था कि चार दशकों में चीन ने युद्ध पर एक पैसा भी बर्बाद नहीं किया है. साल 1979 में कार्टर के कार्यकाल में ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग का दौर शुरू हुआ था. आज चीन एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है तथा यह उपलब्धि कारोबार के जरिये हासिल हुई है. परंतु, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इन दशकों में उसने अपनी सामरिक तैयारी पर ध्यान नहीं दिया है. साल 2011 में लीबिया के गृहयुद्ध के दौरान चीन ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए वायु सेना के अत्याधुनिक जहाजों और नौसैनिक बेड़े को भेजा था, जबकि उसके नागरिकों पर कोई बड़ा खतरा भी नहीं था और उनमें से अधिकतर लीबिया से निकल चुके थे. यह पहला मौका था, जब चीन ने किसी सुदूर क्षेत्र में ऐसे सैन्य विमान और युद्धपोत भेजे थे. दरअसल, यह घटना पूर्व चीनी नेता देंग जियाओ पिंग के उस निर्देश से अलग होने का संकेत थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन को अपनी ताकत दिखाने से परहेज करना चाहिए और चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए. लीबिया की कार्रवाई से दस साल पहले चीन ऐसा कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन अब तो उसके बाद भी करीब एक दशक का समय बीतने को है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग एशिया और अन्य महादेशों में आर्थिक वर्चस्व के विस्तार के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेल्ट-रोड परियोजना और चीन को निर्माण-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर उनका जोर इसी कोशिश का हिस्सा है. इसी के साथ उन्होंने चीनी सेना के ढांचे में भी बड़े फेर-बदल किये हैं. जिनपिंग के भाषणों में अपमानजनक बाहरी हमलों की छाया से निकलकर अब एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी महान चीनी सभ्यता का उल्लेख आम हो गया है. राष्ट्रपति के तेवर उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा को इंगित करते हैं. साउथ चाइना सी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन निरंतर आक्रामक होता जा रहा है. वित्तीय निवेश, वाणिज्य और बड़े देश की छवि के सहारे वह पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत कर रहा है. इस क्षेत्र में अमेरिका की गहरी पैठ है और उसके अनेक सैन्य ठिकाने स्थापित हैं. लेकिन अमेरिकी संरक्षणवाद की नीति से पैदा हुए व्यापार युद्ध से चीन विचलित होता हुआ नहीं दिख रहा है. अमेरिका और चीन की खींचतान पर भारत को पैनी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि चीन दक्षिणी एशिया में अपनी पहुंच बना चुका है. सीमा विवादों के अलावा द्विपक्षीय व्यापार का संतुलन भी चीन की ओर झुका हुआ है. ऐसे में भारत को एशिया को बहुपक्षीय बनाने की दिशा में कूटनीतिक और कारोबारी सक्रियता को गति देने की जरूरत है.

**साउथ चाइना सी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन निरंतर आक्रामक होता जा रहा है. वित्तीय निवेश, वाणिज्य और बड़े देश की छवि के सहारे वह पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत कर रहा है.**

# अमेरिका का मोहरा नहीं है भारत

**पुष्पेश पंत**
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
pushpeshpant@gmail.com

**यह भारत के दीर्घकालीन हित में है कि वह अमेरिकी दबाव का प्रतिरोध करे और ईरानी तेल के आयात में नाममात्र से अधिक कटौती न करे. ईरान को यह संदेश पहुंचाना जरूरी है कि भारत अमेरिका का मोहरा नहीं.**

तुनकमिजाज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक यह फतवा जारी किया है कि ईरान पर लगाये प्रतिबंधों के मद्देनजर सभी देशों को उससे तेल आयात तत्काल बंद कर देना होगा, अन्यथा वह भी आर्थिक प्रतिबंधों की चपेट में आ जायेंगे. अब तक उन्होंने भारत और चीन समेत उन आठ देशों को, जो ईरान से अपनी मुद्रा में तेल खरीद रहे हैं और उसके सबसे बड़े तेल ग्राहकों में हैं, कुछ समय तक ईरानी तेल खरीदने की 'रियायत' दी थी. अंतरिम राहत की यह अवधि अब समाप्त हो गयी है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गयी है, जिसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़े बिना नहीं रह सकता. हालांकि, अमेरिका ने सऊदी अरब के माध्यम से यह भरोसा दिलाया है कि वहां बढ़े तेल उत्पादन के जरिये तेल की कीमतों को नियंत्रित रखा जायेगा.

यहां इस बात की तरफ ध्यान दिलाना जरूरी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून तथा राजनयिक परंपरा का खुलेआम उल्लंघन है, जिसे अघोषित 'युद्ध' के दौरान घेराबंदी के समकक्ष समझा जाना चाहिए. यहां विस्तार से इस बात का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता कि क्यों अमेरिका यह नीति अपना रहा है, बस इतना भर रेखांकित किया जाना जरूरी है कि उसके अनुसार ईरान के सैनिक परमाण्विक कार्यक्रम को बाधित करने के लिए ही उस पर यह अंकुश लगाया गया है. यह सवाल पूछना जायज है कि ईरान की संप्रभुता को संकुचित करने का यह अधिकार अमेरिका को किसने दिया है? ईरान को अपना परमाण्विक ऊर्जा कार्यक्रम इच्छानुसार चलाने की पूरी आजादी है. परमाण्विक अप्रसार संधि की किसी धारा में कोई ऐसा प्रावधान नहीं. जब से रजाशाह पहलवी का तख्ता पलट हुआ और ईरान का कायाकल्प इस्लामी गणराज्य में हुआ, तभी से अमेरिका की दुश्मनी ईरान के साथ चल रही है. जिमी कार्टर के राज में ईरान में अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाकर सालभर तक कैद में रखा गया था और उन्हें सैनिक हस्तक्षेप से रिहा कराने में सर्वशक्तिमान अमेरिका असमर्थ रहा था. बाद के वर्षों में इस्राइल के जरिये ईरान की परमाणु परियोजनाओं को पटरी से उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी.

चीन के बाद भारत ही ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक है. चीन की तेल जरूरतों की छह प्रतिशत आपूर्ति ईरान करता है, जबकि भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 19 प्रतिशत के पास पहुंचता है. जहां चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान निर्णायक भूमिका नहीं निबाहता, वहीं भारत इस तेल के अभाव में सऊदी अरब तथा अमेरिका पर निर्भर हो क्रमशः अपनी स्वाधीनता गंवा देगा. चीन इस समय अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध लड़ रहा है, अतः कुछ विद्वानों का मानना है कि वह अपनी कठिनाई कम करने को ईरानी तेल के आयात में कटौती कर सकता है, परंतु हमारी समझ में वह ऐसा कतई नहीं करेगा, क्योंकि शी जिनपिंग चीन को अमेरिकी महाशक्ति का समकक्ष समझते हैं और भयादोहन के आगे घुटने टेक नहीं सकते. हां, पौने छह लाख पीपे प्रतिदिन से आयात कुछ कम किया जा सकता है, प्रतीकात्मक रूप से मुठभेड़ से बचने के लिए.

भारत के ईरान के साथ रिश्ते सिर्फ आर्थिक-सामरिक नहीं. इनका सांस्कृतिक आयाम भी महत्वपूर्ण है. अमेरिकी दबाव में इनमें खटास आयी है. विडंबना है कि कट्टरपंथी इस्लामी राज्य होने के बावजूद ईरान ने चाबहार बंदरगाह परियोजना का जिम्मा सौंपा है, यह जानते हुए कि समान धर्मावलंबी पाकिस्तान इसे अपने विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यवाही मानता है. कराची के समीप चीन की सहायता से जो ग्वादर बंदरगाह बनाया जा रहा है- मुख्यतः भारत की घेराबंदी के लिए- उसका प्रतितोध चाबहार ही कर सकता है. विश्वव्यापी शिया-सुन्नी वैमनस्य में भी भारत को ईरान अपने साथियों में शुमार करता है. ईरान के बाद दुनिया में सबसे अधिक शिया भारत में ही बसते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घड़ी भारत को याद दिलाया है कि- 'चूंकि हम तुम्हारी मदद अजहर मसूद के प्रत्यर्पण में कर रहे हैं, इसकी एवज में तुम्हें हमारा आज्ञापालन ईरानी प्रतिबंधों के बारे में करना चाहिए.' इस कुतर्क को स्वीकार करना भारत के लिए आत्मघातक हो सकता है. क्या महज एक दहशतगर्द की फिरौती हमारे राष्ट्रहित में सर्वोपरि समझी जा सकती है? क्या अमेरिका के इस आश्वासन को वास्तव में असरदार विश्वसनीय समझा जा सकता है? यह ना भूलें कि इसी अजहर मसूद का चीन के राजनयिक संरक्षण के चलते भारत बाल भी बांका नहीं कर सका है.

किसी भी अन्य संप्रभु राज्य की तरह भारत को अपने शत्रु तथा मित्र तय करने का अधिकार है. किसके साथ हम कैसे संबंधों का निर्वाह करते हैं, ये फैसले किसी और के हाथों गिरवी नहीं रखे जा सकते. एक बार ईरान को बधिया बनाने के बाद अमेरिका की कोई दिलचस्पी भारत के साथ सहकार में नहीं रहेगी. यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि चीन की ही तरह भारत को भी अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए जिम्मेदार ठहराता है. जिन अमेरिकी कंपनियों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत या चीन में उत्पादक इकाइयां स्थापित की हैं, उन्हें लगातार ट्रंप की नाराजगी झेलनी पड़ी है.

चीन के नेताओं ने लंबी लड़ाई के लिए कमर कस ली है. वह जानते हैं कि व्यापार युद्ध तथा आर्थिक प्रतिबंधों की बड़ी कीमत अमेरिका को खुद भी अनिवार्यतः चुकानी ही पड़ेगी! देखना यह है कि पलक पहले कौन झपकाता है! दुर्भाग्य से चुनावों में व्यस्त हमारे नेतागण राजनयिक तथा सामरिक चुनौतियों का सार्थक विश्लेषण करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं. सामरिक के नाम पर उनकी नजर पाकिस्तान से आगे पहुंचती ही नहीं है. हालांकि, भारतीय विदेश सचिव की हाल की चीन यात्रा में निश्चय ही यह मुद्दा भी उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता में उठा होगा, लेकिन यह आशा निर्मूल है कि भारत की कठिनाई कम करने के लिए चीन कुछ करेगा. अंततः उस देश के हितों का सन्निपात पाकिस्तान के साथ अधिक है और रहेगा. चीन हर हाल में दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में भारत को प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने से रोकने का हर संभव प्रयास करेगा. अन्यथा नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार में उसके पैर पसारने की गुंजाइश कम हो जायेगी.

यह भारत के दीर्घकालीन हित में है कि वह अमेरिकी दबाव का प्रतिरोध करे और ईरानी तेल के आयात में नाममात्र से अधिक कटौती न करे. ईरान को यह संदेश पहुंचाना जरूरी है कि भारत अमेरिका का मोहरा नहीं.

# भारत-चीन कारोबार का परिदृश्य

**डॉ जयंतीलाल भंडारी**
अर्थशास्त्री
jlbhandari@gmail.com

**चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करनेवाले देश के रूप में पहचान बनानी होगी. हम आशा करें कि वर्ष 2018-19 में भारत का निर्यात बढ़ने और भारत में चीन से आयात घटने का जो परिदृश्य उभरा है, वह आगामी वर्षों में भी जारी रहेगा.**

दुनिया के अर्थशास्त्री भारत-चीन कारोबार के संबंध में दो बातें रेखांकित कर रहे हैं. एक, पिछले दो दशक में पहली बार वित्त वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में कमी आना भारत के विदेश व्यापार के लिए अच्छा है. दो, चीन ने भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार की अहमियत को गहराई से समझा है. यही कारण है कि भारत द्वारा चीन के ओबीओआर प्रोजेक्ट का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद चीन के विदेश ने 19 अप्रैल को कहा कि चीन भारत के साथ एक विशेष सम्मेलन आयोजित करके दोनों देशों के कारोबार संबंधों को गतिशील करने का प्रयास करेगा.

हाल में प्रकाशित भारत-चीन व्यापार के आंकड़ों के मुताबिक, 2018-19 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 88 अरब डॉलर रहा. यह बात महत्वपूर्ण है कि पहली बार भारत, चीन के साथ व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर तक कम करने में सफल रहा है. भारत का व्यापार घाटा करीब 52 अरब डॉलर रहा. पिछले कई वर्षों से चीन के साथ लगातार छलांगे लगाकर बढ़ता हुआ व्यापार घाटा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था. चीन के बाजार तक भारत की अधिक पहुंच और अमेरिका व चीन के बीच चल रहे मौजूदा व्यापार युद्ध के कारण पिछले वर्ष भारत से चीन को निर्यात बढ़कर 18 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो वर्ष 2017-18 में 13 अरब डॉलर था. चीन से भारत का आयात भी 76 अरब डॉलर से कम होकर 70 अरब डॉलर रह गया.

वर्तमान में चीन भारतीय उत्पादों का तीसरी बड़ा निर्यात बाजार है. वहीं चीन से भारत सबसे ज्यादा आयात करता है. दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 2018-19 में बढ़कर करीब 88 अरब डॉलर पर पहुंच गया. चीन से भारत मुख्यतः इलेक्ट्रिक उपकरण, मेकेनिकल सामान, कार्बनिक रसायनों आदि का आयात करता है. वहीं भारत से चीन को मुख्य रूप से, खनिज ईंधन और कपास आदि का निर्यात किया जाता है. पिछले एक दशक के दौरान चीन ने भारतीय बाजार में तेजी से अपनी पैठ बढ़ाई और अपने सामान का प्रवाह लगातार बढ़ाया, लेकिन 2018-19 में पहली बार चीन से होनेवाले आयात में कमी आयी. अब अप्रैल 2019 में चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार में व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत ने 380 उत्पादों की सूची चीन को भेजी है, जिनका चीन को निर्यात बढ़ाया जा सकता है. इनमें मुख्य रूप से बागवानी, वस्त्र, रसायन और औषधि क्षेत्र के उत्पाद शामिल हैं.

देश और दुनिया के अर्थशास्त्रियों का मत है कि वर्ष 2018 की शुरुआत से ही जहां भारत व चीन के बीच अधिक कारोबार की संभावनाएं बढ़ती गयीं, वहीं भारत से चीन को निर्यात बढ़ने और भारत का चीन के साथ व्यापार असंतुलन कम होने का नया परिदृश्य भी दिखायी दिया है. वर्ष 2018 में भारत-चीन के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ताएं हुईं, जिसने भारत से चीन को निर्यात बढ़ाने तथा भारत-चीन के बीच व्यापार असंतुलन कम करने में प्रभावी भूमिका निभायी है. वहीं, 27 मई, 2018 को भारत ने चीन के सॉफ्टवेयर बाजार का लाभ उठाने के लिए वहां दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) गालियारे की शुरुआत की. आईटी कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने कहा कि चीन में दूसरे डिजिटल सहयोगपूर्ण सुयोग प्लाजा की स्थापना से चीन के बाजार में घरेलू आईटी कंपनियों की पहुंच बढ़ गयी.

एक ओर भारत द्वारा व्यापार घाटा कम करने के लिए चीन से वाणिज्य वार्ता को आगे बढ़ाना होगा, वहीं दूसरी ओर इस समय चीन के बाद भारत के लिए दुनिया का नया कारखाना बनने का जो मौका दिखायी दे रहा है, उसे पकड़ना होगा. भारत के पास कुशल पेशेवरों की फौज है. आईटी, सॉफ्टवेयर, बीपीओ, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स एवं धातु क्षेत्र में दुनिया की जानी-मानी कंपनियां हैं, आर्थिक व वित्तीय क्षेत्र की शानदार संस्थाएं हैं. इसलिए अब भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाना होगा. भारत को दुनिया का नया कारखाना बनने के लिए युवाओं के कौशल विकास, ऊंचे उत्पादन स्तर तथा विकास की तेज रफ्तार पर ध्यान देना होगा. शैक्षणिक दृष्टि से पीछे रहनेवाले युवाओं को कौशल विकास से प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से शिक्षित करना होगा.

चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करनेवाले देश के रूप में पहचान बनानी होगी. हमें अपनी बुनियादी संरचना में व्याप्त अकुशलता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना होगा. चीन की तरह भारत को भी गुड गवर्नेंस की स्थिति बनानी होगी. प्रतिस्पर्धा में सतत सुधार तथा वित्तीय मानदंडों के प्रति जवाबदेही पर ध्यान देना होगा. भारत में बुनियादी ढांचे और महंगे ऋण के अलावा कारोबारी माहौल, श्रम की बढ़ती लागत और लॉजिस्टिक के मोर्चे पर दिक्कतों को दूर करना होगा. हम आशा करें कि वर्ष 2018-19 में भारत का निर्यात बढ़ने और भारत में चीन से आयात घटने का जो परिदृश्य उभरा है, वह आगामी वर्षों में भी जारी रहेगा. आशा करें कि जब चीन ओबीओआर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़कर दुनिया के डेढ़ सौ देशों को संगठित करके अपनी कारोबारी ताकत बढ़ा रहा है, तब भारत भी ओबीओआर से दूरी बनाकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी कारोबारी ताकत को मजबूत करेगा तथा चीन के बाजार में गुणवत्तापूर्ण भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ायेगा.

## बोधि वृक्ष

# तुम प्रेम हो

हम प्रेम में भी सहज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि स्वयं से अंतर्मन की गहराई में नहीं मिल पाये हैं, नहीं पहचान पाये हैं कि हम कौन हैं? हमें यह पता ही नहीं कि हम जिस एक तत्व से बने हैं, वह है प्रेम. जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते, अन्य किसी से भी नहीं जुड़ पाते. सो कोई जब तुमसे प्यार का संबंध रखना चाहे और तुम्हें असहजता लगे, तो वह यही दर्शाता है कि तुम स्वयं से नहीं जुड़े हो और इसी कारण प्रेम पाने में असमर्थ हो. पहले स्वयं प्रेम का सम्मान करना सीखो और जो प्रेम का सम्मान नहीं करते, उन पर बिना समझे प्रेम न्योछावर मत करते फिरो. क्योंकि प्रेम दर्शाना, प्रेम देना भी एक कला है. प्रेम देना यानी प्रेम करना. प्रेम कोई कृत्य नहीं है, अपने अस्तित्व की ही एक अवस्था है. तुम केवल वहां सहजता से, बिना किसी अपेक्षा से रहो और कहो- 'मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारे लिए हूं, तुम जब चाहो उसे ले सकते हो.' तुम में यह मनोबल रहते सब तुम्हें बेहतर समझ सकेंगे. तुम किसी को जबरदस्ती नहीं समझा सकते कि तुम सच्चा प्रेम करते हो. तुम यह समय पर छोड़ दो उनको स्वयं समझने के लिए. जबरदस्ती से समझाने की कोशिश में बात ही उलटी पड़ सकती है! यह मत सोचो कि आप खुद से प्यार नहीं करते. यह किसने कहा? यहां तक कि जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, वे भी खुद से प्यार करते हैं. वे अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए पीड़ा नहीं चाहते. वे पीड़ा सहन नहीं कर सकते. पीड़ा से छुटकारा चाहते हैं. जब लोग दुख सहन नहीं कर सकते, तो इसका सीधा अर्थ है कि वे खुशी चाहते हैं. इस तरह अपने लिए अपने प्यार पर शंका मत करो. कौन कहता है आप खुद को प्यार नहीं करते? यह असंभव है, क्योंकि आप स्वयं प्रेम हो. यह केवल कहीं खो गया है. कहीं आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे हो. और आप सही जगह पर हो. जो हो गया उसके बारे में ज्यादा विश्लेषण मत करो. क्योंकि धरती पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जो पूरी तरह दोष से मुक्त हो. हर कार्य में कहीं ना कहीं कुछ दोष होता ही है.

**श्रीश्री रविशंकर**

## आपके पत्र

### कागज में सीमित है संकल्प पत्र

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो कोर्ट में लंबित मुकदमे खत्म किये जायेंगे और न्याय प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ायी जायेगी ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा. लेकिन सत्ता में रहते हुए पांच साल हो गये, पर इसका कोई समाधान सरकार नहीं निकाल पायी है. न्यायालय में दिन प्रतिदिन मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं. आम जनता को जल्दी न्याय नहीं मिल पा रहा है. लोग रोज कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं. यह स्पष्ट है कि उनकी कही हुई बात अब कागज के पन्नों तक ही सीमित रह गयी है. अब एक बार फिर चुनाव हो रहा है. फिर एक बार मोदी सरकार ने अपने चुनावी समीकरण तैयार करके घोषणा पत्र से जनता को लुभाने का प्रयास किया है. पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म किया जायेगा और राम मंदिर का निर्माण किया जायेगा. लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण गंभीर मसलों को सरकार आज भी नहीं खत्म नहीं कर पायी है. ऐसे महत्वपूर्ण और गंभीर मसलों को लेकर लोकलुभावन वादे करके जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए.

**राहुल उपाध्याय,** बलिया, उत्तर प्रदेश

### प्रवासी भारतीय भी डाल सकें वोट

हम प्रवासी भारतीय लोग विदेशों में रह कर भी भारत के विकास में अहम किरदार अदा करते हैं. बहुत बार बातें हुई कि प्रवासी भारतीय भी वोट डाल सकेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया. हम विदेशों में बैठ कर टीवी पर चुनावी तमाशा तो देखते हैं, पर उसमें हम प्रवासी भारतीयों का कोई रोल नहीं होता. सरकार को समझना चाहिए कि विदेशों में भारतीयों की संख्या करोड़ों में है और सरकार ने इन करोड़ों भारतीयों को वोट देने के मौलिक अधिकार से वंचित रखा है. मैं अखबार के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि हम विदेश में भले रहते हैं, पर हमारे रोम-रोम में भारत बसता है, हमें हमारे वोट देने के मौलिक अधिकार से वंचित न रखा जाये. सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे हम विदेश में रहते हुए भी वोट डाल सकें.

**मो सुभान खान शौकत,** (धनबाद)
अबू धाबी, यूएइ

### मानवता पर नया खतरा

संपूर्ण मानव प्रजाति का इतिहास हमेशा से रक्त रंजित ही रहा है. राज्य के लिए, धन के लिए, औरतों के लिए सदा एक मानव समूह दूसरे मानव समूहों की हत्या करते आया है. बाद में दुनिया को धर्म के नाम पर बांट दिया गया. और इसके बाद सामूहिक हत्याओं का सिलसिला तेजी से चल पड़ा. न्यूजीलैंड में ईसाई चरम पंथियों द्वारा निरपराध मुस्लिम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करके हत्या कर दिये जाने के ठीक 37 दिन बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आठ जगह सीरियल बम बिस्फोट करके 250 से अधिक निरपराध लोगों की हत्या कर दी गयी. खुद मर कर मारने वाले आतंकी को बहकाने और उकसाने वाले आइएसआइ के सरगना ही मूल रूप से दोषी हैं. चरमपंथी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है.

**निर्मल कुमार शर्मा,** गाजियाबाद

## कुछ अलग

# रिश्तों की अहमियत

**आनंद मोहन मिश्र**
उपप्राचार्य
santoshutsuk@gmail.com

**आजकल** के व्यस्तता भरे जीवन में लोगों के पास समय कम है. इसलिए रिश्तों की गर्मजोशी भी कम होती जा रही है. हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों तक का एहसास नहीं है.

द्वापरयुग में भगवान श्रीकृष्ण का जीवन देखने से लगता है कि जीवन में कितने रिश्तों को उन्होंने कितनी अच्छी तरह निभाया है और मिसालें कायम की हैं. रिश्तों की अहमियत श्रीकृष्ण से सीखना चाहिए. सुदामा, रुक्मणी, बलदेव, अर्जुन, सुभद्रा, द्रौपदी, राधा, सब मिसालें हैं.

सुदामा जी के साथ उन्होंने मित्रता रूपी रिश्ते को निभाया. जब सुदामा को मित्र की आवश्यकता पड़ती है, तो वह कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन संकोचवश कुछ मांगते नहीं हैं. लेकिन, श्रीकृष्ण सब समझ जाते हैं. यहां दोनों ने एक-दूसरे को समझा है या समझने की कोशिश की है. रिश्तों को बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है. अगर हम अपने मित्र की इच्छाओं की कद्र करेंगे, तो हमारे रिश्ते की डोर और मजबूत होगी.

द्रौपदी भरी सभा में बेबस तथा असहाय थी. कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था. तब उसने विश्वास के साथ गोवर्धनधारी को याद किया. रिश्तों में विश्वास का होना जरूरी है. यदि उस वक्त श्रीकृष्ण नहीं आते, तो परिणाम क्या होता, इस कल्पना से ही मन सिहर उठता है. कुछ लोग कहते हैं कि वे पहले भी आकर द्रौपदी की इज्जत बचा सकते थे. मगर, सीधी बात यह है कि पहले द्रौपदी का विश्वास अपनों के ऊपर था.

बलदेवजी को घूमना पसंद था. श्रीकृष्ण और बलदेव के स्वभाव में कोई समानता नहीं है. लेकिन श्रीकृष्ण ने कभी भी उनके रास्ते में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया. बड़े भाई के संबंध को मधुरता से निभाया.

श्रीकृष्ण अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझते थे. राधा के साथ उनका प्रेम जग जाहिर है. लेकिन यह आध्यात्मिक प्रेम है. प्रेम संबंधो में उन्होंने जो पवित्रता बनाये रखी, वह आज के समय के लिए एक उदाहरण है. निष्कपट, निश्छल प्रेम का अनूठा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है. बिना राधा के आज श्रीकृष्ण के नाम की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं. वहीं अर्जुन रिश्ते में बहनोई एवं मित्र दोनों है. वे चाहते तो रिश्तेदारी निभाने के लिए खुलकर पांडवों का साथ दे सकते थे. लेकिन तब इतिहास उन पर हंसता. दुर्योधन से भी उनकी मित्रता थी. अतः उन्होंने बड़ी सावधानी से गुटनिरपेक्ष रहने का फैसला लिया. उनके इस निर्णय से वे तटस्थ रहे तथा समझदारी से अपनी रिश्तेदारी को निभाया.

पत्नियों रुक्मिणी तथा सत्यभामा में कभी किसी बात को लेकर विवाद न हो जाये, इसका उन्होंने हमेशा ध्यान रखा. सत्यभामा और रुक्मिणी ने अपने लिए श्रीकृष्ण से प्यार किया, इसलिए कहीं-न-कहीं उन्हें श्रीकृष्ण की पत्नी होने का गर्व भी हुआ. और श्रीकृष्ण ने उनके गर्व का हरण भी किया.

सामाजिक संरचना में रिश्तों की बड़ी अहमियत है. प्रेम के महीन रेशों से बुने ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं. हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों का रूप चाहे जो भी हो, ये सभी विश्वास, आदर, ईमानदारी एवं समर्पण की मांग करते हैं.

## देश दुनिया से

# फिलिस्तीन और अमेरिकी योजना

**मध्य-पूर्व** संघर्ष के हल के लिए नयी योजना की तैयारी करते हुए पिछले दो वर्षों में ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीनियों पर चौतरफा कूटनीतिक हमला किया है. दावा किया गया है कि यह योजना दूसरों से अलग है. लेकिन, फिलिस्तीनियों को मालूम है कि इस योजना में क्या होगा. उन्होंने देखा है कि कैसे उन्हें नीचा दिखाने और अपमानित करने के इरादे से ट्रंप प्रशासन ने एक के बाद एक नीति बनायी है. पिछले डेढ़ वर्षों में ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को कई राजनीतिक तोहफे दिये हैं. दिसंबर 2017 में उनके प्रशासन ने जेरुशलम को इस्राइल की राजधानी माना और मई 2018 में अमेरिकी दूतावास तेल अवीव से स्थानांतरित कर दिया. जनवरी 2018 में, लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहारा देनेवाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को दी जानेवाली सहायता पर रोक लगा दी. उसने इस्राइल के खिलाफ पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् छोड़ दिया. इसी बीच वेस्ट बैंक में यहूदी बस्ती के विस्तार के लिए नेतन्याहू को खुली छूट दे दी. इस वर्ष चुनाव से ठीक पहले, ट्रंप ने सीरियाई गोलन हाइट्स पर इस्राइल कब्जे को मान्यता भी दी.

**मार्वन बिशारा**

## कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

**पोस्ट करें** : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
**मेल करें** : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है